जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका

डॉ० शिवानी
एसोसिएट प्रोफेसर
डी०ए०वी० सैन्टेनरी कॉलिज, फरीदाबाद
ईमेलः shivanitanwar1973@gmail.com

सारांश

मीडिया को अगर आज जिस शक्ति की बात होती है वह उसे जन भावना के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। मीडिया जनभावनाओं को जितनी ईमानदारी से अभिव्यक्त करेगा, उसको सामने लाएगा, उतनी ही इसकी स्वीकार्य ता बढ़ती हैं। इसी स्वीकार्यता के जरिये मीडिया लोगों में अपनी पैठ बनाता है। भारत के स्वाधीन होने के बाद सबसे अधिक प्रयास भारत के लोकतान्त्रिक व्यवस्था मजबूत करने में किया गया। उस दौरान भारतीय मीडिया का जो भी स्वरूप मौजूद था उसके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती में सहयोग देना। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार कार्यकर्ताओं की बहुलता होती है जो एक स्थिति में एक दूसरे से अन्तः क्रिया करते हैं। इस समय व्यवस्था में अनेक उपव्यवस्थाएँ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यक्तिगत आदि होती हैं जिनकी रूपरेखा वृहत् सामाजिक व्यवस्था के समान ही होती हैं। भारतीय समाज धर्म, जाति, भाषा, प्रजाति आदि दृष्टि से बहुलतावादी समाज है जो अपने अलग–अलग राजनीतिक हितों में बँधी हुई है। यद्यपि संवैधानिक दृष्टि से सम्पूर्ण भारत एकता और अखण्डता के आदर्श से अलंकृत है परन्तु इसके निवासियों के राजनीतिक हित, राजनीतिक चेतना एवं मतदान व्यवहार में बहुरंगी विविधता देखने को मिलती हैं परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अस्मिता के लिए सम्पूर्ण भारत एकता की कड़ी में बंधा है। चुनाव एवं निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बंधित एक अन्य पहलू मतदान आचरण है। यह विदित है कि मतदान व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का सामूहिक निर्णयों में समाहार करने का एक साधन है। जनमत व्यवहार से अभिप्राय मतदाता के मत देने तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन से है।

मुख्य बिन्दु

जनमत व्यवहार, मीडिया, लोकतंत्र, मतदान आदि।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 24.02.2023
Approved: 21.03.2023

डॉ० शिवानी

जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका

RJPP Oct.22-Mar.23,
Vol. XXI, No. I,

pp.102-110
Article No. 14

Online available at *:*
https://anubooks.com/rjpp-2023-vol-xxi-no-1

प्रस्तावना

लोकतंत्र की चेतना जिस एक शब्द के केंद्र में समाहित है वह है जनमत। जनमत में ही लोकतांत्रिक शक्तियों की वह शक्ति निहित है जिसके जरिये हांशिये पर खड़े लोग सत्ता के केन्द्र तक पहुंच जाते है। क्योंकि जनमत ही वह ताकत है जो यदिसत्ता के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ हो जाए तो उसे अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगता। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकांश देशों में जब बदलाव की लहर चलती है तब जनमत के दबाव में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के बगैर भी बदलाव हुये हैं। लोकतंत्र का जन्म ही जनमत की इस शक्ति के बल पर प्राप्त हुआ है और यह तथ्य स्वयं सिद्ध है कि लोकतंत्र की सफलता जनमत के सहयोग के बगैर बिलकुल भी संभव नहीं है। दूसरी तरफ मीडिया वह महाशक्ति है जो दुनिया पर सबसे अधिक प्रभाव डाल रही और उसके बदलाव को दिशा दे रही हैं।

भारत के स्वाधीन होने के बाद सबसे अधिक प्रयास भारत के लोक तान्त्रिक व्यवस्था मजबूत करने में किया गया। उस दौरान भारतीय मीडिया का जो भी स्वरूप मौजूद था उसके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती में सहयोग देना। मीडिया ने इस क्षेत्र मे बड़ बड़े कार्य भी किए लेकिन कालांतर में मीडिया के सामने जब कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था तब धीरे–धीरे मीडिया का राजनीति के संबंध निर्मित होने लगा। हालांकि इससे पहले भी राजनीति और मीडिया के संबंध थे परंतु यह संबंध स्वाधीनता आन्दोलन में एक–दूसरे के सहायक के संबंध के रूप में थे। स्वतंत्रता के बाद इन सम्बन्धों में काफी परिवर्तन आया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मीडिया में राजनीतिक प्रभाव का असर दिखने लगा। गाँव और दूरदराज की खबरें उनके लिए बहुत महत्व नहीं रखती थी। वस्तुतः आजादी के बाद मीडिया ने बहुपक्षीयता से एक पक्षीय रूझान किया। यानी राजनीतिक खबरें ज्यादा स्थान लेने लगी। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार कार्यकर्ताओं की बहुलता होती है जो एक स्थिति में एक दूसरे से अन्तः क्रिया करते हैं। इस समय व्यवस्था में अनेक उपव्यवस्थाएँ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यक्तिगत आदि होती हैं जिनकी रूपरेखा वृहत् सामाजिक व्यवस्था के समान ही होती हैं। इन उप व्यवस्थाओं में घनिष्ठ एवं जटिल सम्बन्ध पाये जाते हैं जो कि प्रत्येक स्तर पर दृष्टिगोचर होते हैं। भारतीय समाज धर्म, जाति, भाषा, प्रजाति आदि दृष्टि से बहुलतावादी समाज है जो अपने अलग–अलग राजनीतिक हितों में बँधी हुई है। यद्यपि संवैधानिक दृष्टि से सम्पूर्ण भारत एकता और अखण्डता के आदर्श से अलंकृत है परन्तु इसके निवासियों के राजनीतिक हित, राजनीतिक चेतना एवं मतदान व्यवहार में बहुरंगी विविधता देखने को मिलती हैं परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अस्मिता के लिए सम्पूर्ण भारत एकता की कड़ी में बंधा है। चुनाव एवं निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बंधित एक अन्य पहलू मतदान आचरण है। यह विदित है कि मतदान व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का सामूहिक निर्णयों में समाहार करने का एक साधन है। जनमत व्यवहार से अभिप्राय मतदाता के मत देने तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन से है।

साहित्य समीक्षा

रेणुका नैयर 2002 दूरस्थ संचार के क्षेत्र में तेजी से हो रही विकास के कारण परिवर्तन का संदेश देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा है यह लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न संस्कृतियों

को संजोये हुए हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी ओर विशेषज्ञों का यह मानना है कि पत्रकारों का झुकाव शहरों की तरफ अधिक होता है शहरों में घटी घटनाएं, उनकी समस्याएं और राजनीति के चक्रव्यूह आदि पत्रकारों को अधिक आकर्शित करते हैं जबकि गांवों में बिजली, पानी की समस्या, जात–पात के झगड़े, छोटे किसानों की आर्थिकदशा, खाद–बीज का न मिलना, बैंक ऋण पानेमें बाधाएं, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं का अभाव, कृषि मजदूरों और महिलाओं की समस्याएं सरकारी योजनाओं की जानकारी न होना आदि विषय हैं जिन्हें पत्रकार कभी–कभार ही छूते हैं।

आधुनिक मीडिया दृष्टि 2005 में लेखक कृष्ण कुमार ने लिखा है कि संचार माध्यमों की इस अनूठी–अनोखी दुनिया का पहला सम्मेलन रेडियोथारेडियो के सम्मोहन ने पहली बार लोगों को एक–दूसरे के पास लाने की पहल की। लेखक संचार माध्यमों की अच्छाइयों व बुराइयों पर बात करते हुए विभिन्न बिन्दुओं को छूते हैं। उनके अनुसार यदि यह संस्कृति हमारे यहां पनपती भी है तो पर्याप्त समय तक नगरों तक ही सीमित रहेंगी। गांवों में जहां हमारी पचहत्तर फीसदी आबादी है वहां तक इसका जन्म और विकास बीसवीं सदी में असम्भव बात है।

सुभाष कश्यप 2005 ने पुस्तक में भारतीय राजनीति के सामाजिक आधारों का वर्णन किया गया है। भारतीय राजनीति के सामाजिक आधारों, ऐतिहासिक आधार, जाति एवं वर्ग व संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक दलों का विश्लेषण किया गया है। राजनीतिक दलों में जनसंघ, जनतादल और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य व बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर विशुद्ध विवेचन प्रस्तुत पुस्तक में दिया गया है। भारतीय राजनीति के विशेष क्षेत्र की विविध समस्याओं व मुद्दों को प्रकाशित किया गया है। राजनीतिक संस्थाओं प्रक्रियाओं का बदलते भारतीय राजनीतिक परिवेश में समझने का प्रयास किया गया।

हिमांशु शेखर 2012 ने भारत में मीडिया की भूमिका पिछले दशको में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है परंतु इस बदलाव में मीडिया ने अपने स्वरूप को लेकर निष्पक्षता से कितना निर्वाह किया है यह समझने वाली बात है। यह भी शासक जातियों के वर्चस्व को बनाए रखने का माध्यम बन गया है। मीडिया सामाजिक हित के महत्वपूर्ण मुद्दों को उपेक्षित करके अनर्गल बहसों को हवा देकर जनता का ध्यान बंटाने की कोशिश कर रहा है। पुरातन पंथी दकियानूसी, अंधविश्वासी संस्कारों को वैज्ञानिक तकनीक के सहारे पुनर्स्थापित करने की कोशिश मीडिया द्वारा की जा रही है। मीडिया का प्रबंध तंत्र, प्रचार तंत्र, प्रसार तंत्र अपने जातिगत और वर्गगत हितों की पूर्ति करता है। मीडिया लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करें तभी उसकी सार्थकता है अन्यथा उसकी छवि शासन जातियों के भोंपू के रूप में बनी रहेगी। लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ के रूप में मीडिया निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करे एवं सरकार व नागरिकों के बीच सेतु के रूप कार्य करके लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं।

जोसेफ गाथिया 2009 पुस्तक में लेखक ने लिखा है कि सार्वजनिक दायरा हमें हमारे समुदाय में होने वाली घटनाओं एवं अपराध की जानकारी देता है और सामाजिक, सांस्कृतिक और

राजनीतिक मुद्दों से हमें परिचित कराता है। यह समाज के विभिन्न मुद्दों पर सहमति व आमराय बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। सार्वजनिक दायरा लोगों को एहसास करवाता है कि उन्हें किन मुद्दों पर विचार करना है और विभिन्न मुद्दों पर किस दृष्टिकोण से सोचना है। जनसंचार माध्यमों के कारण ही करोड़ों लोग प्रतिदिन होने वाली घटनाओं से परिचित होते हैं और उन पर विचार–विमर्श करते है।

कालू राम परिहार 2010 ने पुस्तक में लिखा हैं कि मीडिया को दलितों की याद उसी समय आती है जब आरक्षण संबंधी मुद्दे पर विरोध को हवा देनी हो या फिर उनसे कोई व्यावसायिक राजनीति कला भले ना हो। वे मानते हैं कि मीडिया दलितों के प्रति काफी असंवेदनशील है और न केवल दलित, दलित समुदाय पर अत्याचार की घटनाओं को नजर अंदाज करता है न बल्कि दलितों की उपलब्धियों और सामाजिक योगदान को भी उचित महत्व नहीं देता। वे लिखते हैं कि मीडिया में सर्वोच्च पदों पर उच्चजातियों के लोग हैं। जिनमें दलितों और आदिवासियों के लिए कोई स्थान नहीं है। राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख पदों में से एक पर भी दलित या आदिवासी नहीं है।

जबरीमल पारीख 1996 ने पुस्तक मेंसंचार की अवधारणा, परिभाषा और संचार के कार्य के बारे में बताया गया है। संचार के प्रकार, प्रक्रिया एवंतत्व, संचार के चरण एवं मॉडल के संबंध में वर्णन है। प्रमुख अवधारणा के रूप में संज्ञानात्मक सामंजस्य, नियामक सिद्धांत जैसे प्रभुत्ववादी सिद्धांत साम्यवादी सिद्धांत, मार्क्सवाद और मासमीडिया, सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, और लोकतांत्रिक सहभागिता मीडिया का सिद्धांत का भी वर्णन है।

ममता तिवारी 2012 ने पुस्तक में चुनाव लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। बगैर चुनावी प्रक्रिया के कोई भी लोकतंत्र नहीं रह सकता है। लोकतंत्र में चुनाव और चुनाव में मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। आजादी के बाद लोकसभा के पहले आम चुनाव से लेकर आज तक होने वाली लोकसभा चुनाव में मीडिया अपनी भूमिका को बढ़ाती जा रही है। मीडिया के वर्चस्व कायम है और आने वाले दिनों में इसकी भूमिका और जनता की आवाज को समाहित किया गया है।

राजीव रंजन 2013 ने इस पुस्तक में राजनीति की स्वतंत्र सत्ता, भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में शासन की सक्रिय भूमिका, सामाजिक परिवर्तन लाने में शासन की क्या नीतियां व कार्यक्रम होंगे जिससे सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है एवं इस परिवर्तन का राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय राजनीति की अपनी शक्तियों, पश्चिमी ढांचे के वर्गहितों के समुच्चयीकरण और आर्थिक शक्तियों की प्रभुता में मार्क्सवादी ढांचे का अन्य ढांचे से भिन्नता का वर्णन किया गया है।

जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 2017 हिंदी पत्रकारिता का इतिहास पुस्तक में भारतवर्ष में पत्रकारिता के प्रवेश के साथ ही हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। भारत में छापे खाने पहले ही आ चुके थे। बंबई में सन् 1674 में एक प्रेस की स्थापना हुई और मद्रास में सन् 1772 में एक प्रेस स्थापित हो चुका था। उस समय भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के सामने अनेक समस्याएँ थीं, जबकि वे नया ज्ञान अपने पाठकों को देना चाहते थे। उस काल में ज्ञान साथ–साथ समाज–सुधार की भावना भी उन लोगों में थी। सामाजिक सुधारों को लेकर नए और पुराने विचार वालों में अंतर भी होते थे, जिसके कारण नए–नए पत्र निकाले गए। हिंदी के प्रारंभिक संपादकों के सामने एक समस्या यह भी थी कि भाषा शुद्ध हो और सबको सुलभ हो।

विष्णु राज गढिया 2008 जन संचार माध्यमों ने अपनी अहमियत से सभी को परिचित करा दिया है। इसके एक नई संस्कृति को विकसित करने की कोशिश की है जिसे मीडिया के सशक्तिकरण की संस्कृति कह सकते हैं। आज इसके कारण ही मानव अधिकारों के बहुत सारे संवेदनशील मामले सामने आए हैं। जन संचार माध्यमों अथवा मीडिया के द्वारा आम जनता को जागरूक बनाया जाता है। जनसंचार माध्यमों या मीडिया को मानवाधिकारों के संरक्षण का एक मंच भी कहा जा सकता है। जनसंचार माध्यमों के दृष्टि तथा जनकल्याण योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभाने की सतत् प्रक्रिया चल रही है।

Pranoy Roy, Dorab R, Sopariwal 2019 के आम चुनाव से ठीक कुछ पहले प्रकाशित हुई थी। यह किताब मुख्यतः आम वोटरों के चुनावों में भूमिका पर प्रकाश डालती है। भारत का वह गरीब और बंचित तबका जो हाशिये पर है वहीं चुनावों में सब से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और यही भारतीय चुनावों की खूबसूरती और लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।

Shivam Shankar Singh, 2019 यह किताब राजनीति और चुनाव के परंपरागत विषयों से काफी हटकर है परंतु वर्तमान समय में चुनाव पर काफी प्रभाव डालने वाले विषयों पर लिखी गई यह किताब मुख्यतः सोशल मीडिया के माध्यम से और आंकड़ों का विश्लेषण करके चुनाव पर कैस`प्रभाव डालें इस पर आधारित है।

Rajdeep Sardesai, 2019 यह पुस्तक मोदी सरकार की दुबारा सत्ता में आने के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालती है। लेखक के अनुसार मोदी सरकार का दोबारा सत्ता में आना एक चमत्कार कथा कुछ लोगों के लिए पूर्व निश्चित परिणाम था। लेखक आगे कहते हैं कि परिणाम की विवेचना करना बहुत जल्द जरूरी है क्योंकि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत लाने में सफल हुई। चुनाव किन मुद्दों पर आधारित है। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विकास या फिर राष्ट्रीय गौरव । राजदीप सरदेसाई ने इस पुस्तक कोबड़े सरल शब्दों में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है तथा यह पुस्तक हमें 2019 के चुनाव में तो हम कह सकते हैं कि 2014 के चुनाव ने भारत को बदला परन्तु 2019 के चुनाव में नए भारत की नीव डाली।

अध्धयन की आवश्यकता

मीडिया और राजनीति दोनों का प्रत्यक्ष संबंध आम जनता से है जिसको वह प्रभावित करती हैं। मीडिया और उसके जनमत निर्माण की प्रक्रिया भी आम जनता के बीच ही सम्भव हो पाती है। मीडिया ने भारत की जनता के सामाजिकता को पिछले दो दशक में सबसे अधिक प्रभावित किया है। राजनीति और उससे जुड़े कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आम जनता तक पिछले दो दशक में खूब सम्भव हुआ है। यही नहीं नव संचार साधनों के आने से आम जनता के विचार, निर्णय और उनके सोचने समझने की क्षमता को जानने का मौका मीडिया के माध्यम से मिलने लगा। जिसे क्या पसंद आ रहा है यह मीडिया के जरिए सामने आने लगा। किसी बड़ी घटना से लेकर राजनीति के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण मीडिया के जरिए होने लगा।

अध्धयन के उद्देश्य

मीडिया और उससे जुड़े दूसरे हिस्से भी आज सूचना क्रांति के प्रभाव से बच नहीं पा रहे

हैं। मौजूदा समय में मीडिया व्यवसायिक रूप से सामने आया है जहां वह मीडिया, पत्रकारिता से जुड़े नैतिकता और सच्चाई को पीछे रख व्यवसायिक तौर पर सबसे आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। जिसका स्पष्ट प्रभाव समाज पर है और उसके जनमत पर है। इसलिए इसके सामाजिक प्रभाव पर अध्ययन जरूरी जान पड़ता है। जनमत निर्माण के संबंध में मीडिया का प्रभाव क्या है आम जनता को उसकी राजनीतिको तय करने में मीडिया की क्या भूमिका है एवं मीडिया का जनमानस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है इन प्रश्नों को जानने समझने के लिए अध्ययन जरूरी है।

मीडिया और जनमत निर्माण

मीडिया आधुनिक सभ्यता का प्रमुख साधन हैं जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्र करना संपादित करना और सम्यक प्रस्तुतीकरण आदि सम्मिलित हैं। आज के युगमें टीवी, प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक सहित मीडिया के भी अनेक माध्यम हो गए है। सामाजिक सरोकारों तथा सार्वजनिक हित से जुड़कर ही मीडिया सार्थक बनती है। सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुँचाने और प्रशासन की जनहित कारी नीतियों एवं योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का दायित्व मीडिया के पास हैं। मीडिया कोलोकतन्त्र में यह महत्वपूर्ण स्थान अनायास नहीं मिला है बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्व को देखते हुये समाज ने यह महत्व मीडिया या पत्रकारिता को प्रदान किया हैं। किसी भी लोकतंत्र के मजबूत होने के पीछे जो सबसे बड़ी भूमिका है वह मीडिया के मजबूत होने के उपरांत ही होती है।

सूचनाओं का मानव सभ्यता के विकास में हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनुष्य सूचनाओं की व्याख्या करने में कि सहद तक सक्षम होता है और उसके ऊपर सूचनाओं का कितना प्रभाव पड़ता है, यह मुद्दा हमेशा से दार्शनिक, समाज शास्त्रीय, मनोविज्ञान विश्लेषकों एवं मीडिया चिंतकों को आकर्षित करता रहा है। यह विषय और भी महत्वपूर्ण बन जाता है जब सूचनाओं का प्रयोग शक्ति एवं सत्ता के निर्धारण के लिए आवश्यक औजार साबित होता है। महान यूनानी दार्शनिक सुकरात, प्लेटों या अरस्तू सभी ने अपनी शिक्षण व्यवस्था में एक राज्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जनमत सामाजिक अंतर्क्रियाओं का प्रतिफलन है। जनमत कभी भी अचानक या तुरंत में घटने वाली घटना की तरह नही होता बल्कि इसके निर्माण में एक समयावधि भी लगती हैं। जनमत जन और मत के योग से बना है, इसलिए जनमत को समझने के लिए इन दो पदों को भी समझना अनिवार्य होगा। जनजनता शब्द को परिभाषित या व्याख्यायित करना कोई सरल कार्य नहीं हैं।

जनमत निर्माण के संबंध में यह सर्वविदित है कि जनमत सामाजिक अंतर्क्रियाओं का प्रतिफलन है। जनमत कभी भी अचानक या तुरंत में घटने वाली घटना की तरह नही होता बल्कि इसके निर्माण में एक समयावधि भी लगती हैं। जनमत जन और मत के योग से बना है, इसलिए जनमत को समझने के लिए इन दो पदों को भी समझना अनिवार्य होगा। जनजनता शब्द को परिभाषित या व्याख्यायित करना कोई सरल कार्य नहीं हैं। भारत एक लोक तांत्रिक देश हैं, जहाँ सरकार का गठन संसदीय चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है। सामाजिक व्यवस्था वैयक्तिक कर्ताओं की बहुलता होती है जो एक स्थिति में एक दूसरे से अन्तः क्रिया करते हैं। इस समाज व्यवस्था में

अनेक उपव्यवस्थाएँ जैसे राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृतिक आदि होती हैं जिनकी रूपरेखा वृहत् सामाजिक व्यवस्था के समान ही होती हैं।

जनमत निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के लिए वह आधार प्रस्तुत करता है जिसमें लोकप्रिय सम्प्रभुता पुष्पित–पल्लवित होती है। यह सत्ताधारी पार्टी के विरोध या समर्थन पर आधारित मतदाताओं का व्यक्तिगत निर्णय होता है। जिसकी सामूहिक परिणीति जनादेश के रूप में होती है। इस जनादेश के अनुरूप ही शासक वर्ग से नीति निर्धारण एवं प्रशासक वर्ग से राजनीतिक व्यवस्था के संचालन की अपेक्षा की जाती है। मत व्यवहार जनप्रतिनिधियों में दायित्व बोध उत्पन्न करता है। राजनीतिक दलों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करता है। मतदान व्यवहार ही प्रमुख तत्व है जो निर्वाचन को विकृत या आदर्श स्वरूप प्रदान करता है और अन्ततः लोकतंत्र की सार्थकता या निरर्थकता के लिये उत्तरदायी होता है।

भारतविश्व के उन देशों में हैं जहां लोकतंत्र अपने वजूद के साथ दिनों दिन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। सामान्य तौर पर लोकतंत्र का अर्थ लोकप्रिय सम्प्रभुता पर आधारित शासन व्यवस्था से लिया जाता है। यह वह शासन व्यवस्था है जहां व्यवस्था का जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालन होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मिले विभिन्न अधिकार व संवैधानिक स्वाधीनता प्राप्त होती है। भारतीय लोकतंत्र के शासन व्यवस्था के तहत विभिन्न उतार चढ़ाव को देखने के बावजूद मीडिया ने वर्तमान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित की है। मीडिया की स्वतंत्र हो ना लोकतांत्रिक चेतना के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, यह लोकतंत्र का आधार है। मीडिया संसार में तथा हमारे चारों ओर घटित होने वाली सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियों के प्रति हमें न सिर्फ जागृत करता है बल्कि वह समाज के वास्तविकता से भी परिचित कराता है। जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण होता है उसी तरह मीडिया भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का वह दर्पण है जो हमें जीवन के कटुसत्य और यथार्थपरक वास्तविकताओं को हमें दिखाता है या उसका प्रयास करता है।

संचार एक गतिशील प्रक्रिया है जो संबंधों पर आधारित है यह संबंध जोड़ने का पुल भी है जिस पर चलकर सम्बन्धों की आवाजाही होती हैं। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से एक समूह को दूसरे समूह से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना संचार का कार्य है। जनसंचार का अर्थ सूचनाको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। जनसंचार ही बताता है कि राजसत्ता या शासन की व्यवस्था का आधार क्या हो? सरकार का रूप कैसा हो, स्वेच्छाचारी राजा या सैनिक अधिकारियों का शासनहो या स्वतंत्र और लोकप्रिय सरकार हो जनसंचार माध्यम से ही यह पता चलता है।

जनमत निर्माण सिद्धांत की प्रासंगिता आज भी उतनी ही है जितनी पहल`हुआ करती थी। नई सूचना तकनीक के आगमन से आज सूचनाओं पर कुछ शक्तिशाली वर्ग का आधिपत्य नही रह गया है। आज जनता भी सूचनाओं को जल्द से जल्द प्राप्त करती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार हमेशा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और यहाँ चुनाव आवश्यक होते हैं। आज चुनावी अभियान ज्यादा सुनियोजित हो गए हैं परंतु अभी भी चुनाव का मुख्य खर्च विज्ञापन एवं रैली पर ही होता है। अपने संदेशों को जनता तक पहुँचाना और उनका विश्वास जितना ही राजनीतिज्ञों का प्रमुख

उद्देश्य होता है। चुनाव अभियान में राजनेता अपने भाषण द्वारा जनता को अपने हक में वोट देने का अनुनय करता है और उसे अपना भाषण ऐसे तैयार करना होता है जिससे वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं का विश्वास जीत सकें। जनता उसी राजनेता पर विश्वास करती है जिससे वो एक जुड़ाव महसूस करती है और जो अपने चरित्र एवं अपने पूर्व कार्यों से एक भरोसेमंद पात्र साबित हो। मीडिया के प्रत्यक्ष एवं सीधे प्रभाव को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता क्यूँ कि विश्व के अनेकों चुनाव अभियान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मीडिया जनमत निर्माण की आँधी को हवा देने में सफल होती है। कोई भी चुनाव अभियान सिर्फ रैली, भाषण या मीडिया के दम पर नही जीता जा सकता, ओपिनीयन लीडर्स का एक खास महत्व है। सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता उस पार्टी के प्रचारक की भूमिका निभाते हैं जो अपने काम एवं अपनी बातों से जनता को अपनी ओर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे गाँव–शहर में ओपिनीयन लीडर्स बन सकने वाले व्यक्ति का चुनाव करते हैं और उन्हें अनुनय–विनय एवं प्रत्यायन तकनीक का प्रयोग कर अपने पक्ष में प्रचार करने को प्रेरित करते हैं। अतः जनमत निर्माण सिद्धांत संचार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका आकर्षण हर दौर के समाजशास्त्री को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है।

लोकतंत्र का एक बड़ा साधन चुनाव है और मीडिया पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में अति सक्रिय हुआ है। टी0वी0 न्यूज चौनल्स निर्वाचन से पूर्व राजनीतिज्ञों को उनके द्वारा किये गये वायदों को याद दिलाते हैं और जनसाधारण विशेष रूप से निरक्षर व्यक्ति को सही व्यक्ति का निर्वाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों को अपने आश्वासनों को पूरा करने का दबाव डालते हैं। मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के छिद्र बिन्दुओं को उजागर कर सरकारको उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करती है और सरकार को अधिक जवाब देह, उत्तरदायी और नागरिकों के अनुरूप बनाने के सहायता करती है। मीडिया के बिना लोकतंत्र बिना पहिये के वाहन के समान है। मीडिया ही स्वस्थ जनमत निर्माण का साधन है। मीडिया ने भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों एवं सदस्यों के नैतिक अवमूल्य एवं भ्रष्टाचार को अपने स्टिंग आपरेशन के द्वारा सबके सामने प्रस्तुत किया है। इस तरह के सत्य अन्वेषण एवं तथ्यों की प्रस्तुति से जनता जनार्दन अपने प्रतिनिधियों के कृत्यों से न केवल अवगत होती है वरन् भविष्य के लिए सचेत भी होती है। मीडिया द्वारा किये गये विविध स्टिंग ऑपरेशन में ऑपरेशन दुर्योधन एवं आपरेशन चक्रव्यूह विशेष उल्लेखनीय हैं। मीडिया द्वारा किये गये इन आपरेशन ने हमारे सम्मुख इस तथ्य को रखा कि हमारे नेतागण किस प्रकार अपने विशेषाधिकार को कितने सस्ते में बेचने को तैयार हैं बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि संसद और अपने अधिकार को यह किस नजर से देखते हैं। करीब दस महीने तक चले आपरेशन दुर्योधन ने जाहिर कर दिया कि कैमरे का सही इस्तेमाल करते जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की करतूतों का भंडाभोड़ किया जा सकता है। संसद में सवाल उठाने के नाम पर पैसे लेने वाले सांसदों की सूची जब मीडिया ने जनता के सामने सब प्रमाणों के साथ प्रस्तुत की तो भारतीय लोकतंत्र का बदशक्ल चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया। इसी तरह चक्रव्यूह स्टिंग आपरेशन में सांसद होने के अहंकार में वे यह भूल गए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया भी लोकतंत्र का एक मजबूत आधार स्तम्भ है।"

निष्कर्ष

भूमण्डलीकरण के युग में मीडिया ने समाचार की नई परिभाषा बनाई है समाचार वही जो व्यापार बढ़ाये। बाजार व पूंजी के तर्क मीडिया पर इतने हावी कभी नहीं रहे जितने आज हो गये हैं। आज भारतीय मीडिया परमहत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे बाजार और उपभोक्ता संस्कृति का साथ निभाने वाली मजबूरी के बीच सकारात्मक व समाज को जोड़ने वाली घटनाओं, समस्याओं को प्रमुखता दे और नित घट रही मानवाधिकार हनन की घटनाओं की कवरेज के क्रम में पाठकों को उनके सैद्धान्तिक और व्यवहारिक पहलुओं से अवगत कराये। मीडिया ट्रायल आज भारतीय लोकतंत्र में बड़ी समस्या है। टी०आर०पी० बढ़ाने और मामले के सनसनीखेज प्रस्तुतिकरण के चक्कर में मीडिया अपराधिक मामलों में इतनी खोजबीन कर तथ्य प्रस्तुत करती है कि न्यायालय के निर्णय के पूर्व ही जनमानस के मस्तिष्क में आरोपी बेगुनाह या अपराधी बन जाता है। इस प्रक्रिया में आरोपी के निष्पक्ष ट्रायल के अधिकारों का अतिक्रमण हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का सही रूप में कार्य करना संभव नहीं है। कुछ मीडिया का एक नया चेहरा सामने आ रहा है कि कुछ मीडिया समूह सत्ता पक्ष और मीडिया समूह सत्ता विरोधी हैं और इस विरोध प्रतिरोध की प्रक्रिया में सत्य कहीं पीछे छूट जाता है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ मेंवे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी अनदेखा कर देते हैं। क्या ऐसी मीडिया किसी भी लोकतंत्र व देश की सफलता में सहायक हो सकती है? मुम्बई एवं कश्मीर आतंकी हमले में टी०वी० के एक चौनल ने ऐसी रिर्पोटिंग की जिससे सुरक्षा एजेन्सियों की प्रत्येक गतिविधि आतंकी समूह को प्राप्त होती रही तथा देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी। अन्त में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

सदंर्भ

1. नैयर, रेणुका. (2002). ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता. हरियाणा साहित्य अकादमी।
2. (2005). आधुनिक मीडिया दृष्टि. इंक्लेव पब्लिशर्स।
3. कश्यप, सुभाष. (2005). संसदीय प्रक्रिया. राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
4. जोसेफ, गाथिया. (2009). मीडिया और सामाजिक बदलाव. कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी।
5. परिहार, कालूराम. (2010). मीडिया के सामाजिक सरोकार. अनामिका पब्लिशर्स।
6. पारीख, जबरीमल. (1996). जनसंचार माध्यमों का सामाजिक चरित्र. अनामिका प्रकाशन।
7. तिवारी, ममता. (2012). चुनाव, बुक्स, लोकतंत्र और मीडिया. डायमण्ड पॉकेट।
8. रंजन, राजीव. (2013). चुनाव लोकसभा और राजनीति. ज्ञान गंगा।
9. (2010). 'कुमार, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका.' जनवरी–दिसम्बर. अंक प्रथम–द्वितीय (संयुक्तांक).
10. Roy, Pranoy., Dorab, R-Sopariwala. (2019). THE VERDICT DecodingIndia, selection. Penguin Random House.
11. Noam. (1998). Edward S- Herman. Manufacturing Consent. Patheon books.